भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1000

(जिसका उत्तर सोमवार, 10 फरवरी, 2025/21 माघ, 1946 (शक) को दिया गया)

निजी लिमिटेड कंपनियों के लिए अनुपालन व्यवस्था

1000. श्री विष्णु दत्त शर्मा:

श्री विनोद लखमशी चावड़ा:

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत देश में निजी लिमिटेड कंपनियों के लिए अनुपालन व्यवस्था जी-7 और अन्य विकसित देशों की तुलना में अभी भी बोझिल और जटिल है;

(ख) यदि हां, तो जिन निजी लिमिटेड कंपनियों का कारोबार बहुत मामूली है, बंद होने से पहले दो साल तक उनका कारोबार या लेनदेन शून्य रखना होता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार लंबे इंतजार के समय को कम करने के लिए कोई प्रयास कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): व्यवसाय करने में सुगमता कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निजी कंपनियों के लिए प्रदान की गई अनुपालन अपेक्षाओं का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों ने सार्वजनिक सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों की तुलना में अनुपालन मानकों में छूट दी है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 462 के तहत निजी कंपनियों को अपवाद, संशोधन और अनुकूलन के रूप में विभिन्न छूटों की भी अनुमति दी गई है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, कर्मचारी स्टॉक विकल्प की योजना के तहत कर्मचारियों को शेयरों की पेशकश करने के

लिए विशेष संकल्प के बजाय साधारण संकल्प पारित करना; निजी लिमिटेड कंपनियों आदि को प्रचालनात्मक लचीलेपन की अनुमति देने के लिए बोर्ड की शक्तियों पर प्रतिबंधों से संबंधित अधिनियम की धारा 180 से छूट प्रदान की गई है।

(ख) से (इ):-

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (1) के साथ पठित धारा 248 (2) के अनुसरण में, एक कंपनी निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर कंपनियों के रजिस्टर से अपना नाम हटाने के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकती है, अर्थात्-

- निगमन के एक वर्ष भीतर व्यवसाय शुरू करने में विफलता,
- दो तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए कोई व्यवसाय या संचालन नहीं कर रहा है और धारा 455 के तहत निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त करने के लिए ऐसी अवधि के भीतर कोई आवेदन नहीं किया है,
- ज्ञापन के अभिदाताओं ने उस सदस्यता का भुगतान नहीं किया है जिसका भुगतान उन्होंने निगमन के समय करने का वचन दिया था और निगमन के एक सौ अस्सी दिनों के भीतर इस आशय की घोषणा फाइल नहीं की गई है,
- कंपनी कोई व्यवसाय या संचालन नहीं कर रही है जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 12(9) के फाइल किए गए भौतिक सत्यापन के बाद पता चला है

त्वरित कारपोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र (सी-पेस) की स्थापना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत स्वैच्छिक रूप से नाम हटाने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने और तेज करने के लिए की गई है।

*****